



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 15] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 13, 1994/पौष 23, 1915

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 13, 1994/PAUSA 23, 1915

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1994

सं. 21 (19)/93-रसायन-I:—भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ दावों के पंजीकरण और दावों पर कार्रवाई करने तथा दावों की पूर्ति के मुआवजे के वितरण के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण और कार्रवाई) योजना, 1985 नाम से एक योजना बनायी है। योजना के अनुसार कल्याण प्रायुक्त और उनके अधीन अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं।

सरकार की विभिन्न एजेंसियों यथा आई. सी. एम. आर., राज्य सरकार के कार्यालय, कल्याण प्रायुक्त का कार्यालय की सहभागिता को मद्देनजर रखते हुए भोपाल में दावेदारों को मुआवजा राशि के वितरण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए

एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का होना आवश्यक है तदनुसार सरकार ने एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसके अध्यक्ष श्री एम. एन. कासलीवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे और सर्वश्री न्यायमूर्ति ए. जी. कुरेशी, कल्याण आयुक्त, सचिव (रसायन और पेट्रो-रसायन), सचिव (विधि और न्याय), सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। यह समिति लम्बित दावों के शीघ्रता से निपटाने के मामले को देखेगी और सलाह देगी।

उक्त उच्च स्तरीय समन्वय समिति इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक कार्य करेगी और समय-समय पर ऐसी सिफारिशें करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS

(Deptt. of Chemicals and Petrochemicals)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th January, 1994.

No. 21/19/93-CH.I.—The Government of India have framed a scheme known as the Bhopal Gas Leak Disaster (Registration and Processing of Claims) Scheme, 1985 under the powers conferred by Section 9 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985, for the purpose of, inter alia, registration and processing of claims and disbursement of compensation in satisfaction of the claims. As per the scheme, the aforementioned functions are being performed by the Welfare Commissioner and officers under him.

In view of the involvement of various agencies of the Government, namely, I. C. M. R., Offices of the State Government, Office of the Welfare Commissioner, it is necessary to have a High Level Coordination Committee for the smooth functioning of the work of disbursement of the compensation amount to the claimants at Bhopal. Accordingly, the Govt. have decided to set up a High

Level Coordination Committee with Shri M. N. Kasliwal, Retd. Judge of the Supreme Court of India as Chairman and S/Shri Justice A. G. Qureshi, Welfare Commissioner, Secretary (Chemicals & Petrochemicals), Secretary (Law & Justice), Secretary, Min. of Finance (D/o Expenditure) and the Chief Secretary of the Govt. of Madhya Pradesh as its members. This Committee will look into and advise in the matter of expeditious disposal of pending cases.

The said High Level Coordination Committee will function for a period of one year from the date of this Resolution and make such recommendations from time to time as it may consider necessary.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINOD VAISH, Jt. Secy.

